

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 10-01-2026

विषय सूची

भारत को स्थानीयकृत और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता : प्रधानमंत्री

भारत के डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण

जिला-प्रेरित वस्त्र रूपांतरण (DLTT) योजना

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ 2026

हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में DRDO की बड़ी सफलता

संक्षिप्त समाचार

शक्सगाम घाटी

जल वाष्प

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

वेङ्मार त्रिकोण

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 75 परियोजनाएँ पूर्ण

समग्र शिक्षा 3.0

क्रिएटर्स कॉर्नर

9वीं शीर्ष-स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) बैठक

राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) – NSG

तांबा (Copper)

भारत को स्थानीयकृत और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता : प्रधानमंत्री

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल दिया कि भारत के एआई मॉडल को स्थानीय और स्वदेशी सामग्री के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारत में विकसित एआई नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए और सुदृढ़ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

परिचय

- प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पूर्व आयोजित की गई, जो फरवरी में भारत में होने वाला है।
- बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र

- भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जिसकी वार्षिक आय इस वर्ष 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
- 60 लाख से अधिक लोग टेक और एआई इकोसिस्टम में कार्यरत हैं।
- स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- देश में 1,800+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) हैं, जिनमें से 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं।
 - GCCs मुख्यतः वैश्विक कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र हैं, जो अपनी मूल संस्थाओं को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स हैं, और विगत वर्ष शुरू हुए लगभग 89% नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया।

- NASSCOM एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत का स्कोर 4 में से 2.45 है, जो दर्शाता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं।
- एआई अपनाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं: औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएँ एवं रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, तथा स्वास्थ्य सेवा। ये मिलकर एआई के कुल मूल्य का लगभग 60% योगदान करते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

- एआई मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जो सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता रखते हैं।
- यह प्रणालियों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाता है।
- एआई डेटासेट्स, एल्गोरिद्म और बड़े भाषा मॉडल्स का उपयोग करके जानकारी का विश्लेषण करता है, पैटर्न पहचानता है तथा उत्तर उत्पन्न करता है।
- समय के साथ ये प्रणालियाँ अपने प्रदर्शन में सुधार करती हैं, जिससे वे तर्क कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्यों की तरह संवाद कर सकती हैं।

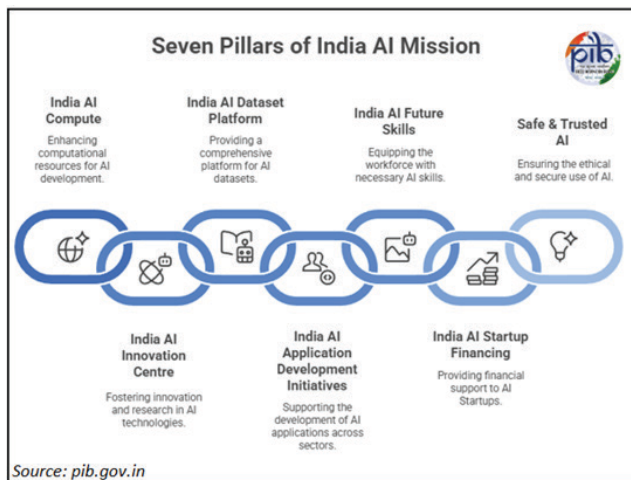
चिंताएँ

- **पक्षपात और भेदभाव:** डेटा पर प्रशिक्षित एआई पक्षपात विकसित कर सकता है और कुछ समूहों के विरुद्ध भेदभाव कर सकता है।
- **डेटा गोपनीयता:** डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के बावजूद भारत में संवेदनशील नागरिक डेटा के लिए व्यापक ढाँचा नहीं है।
- **जवाबदेही का अभाव:** यदि एआई गलत निर्णय लेता है, तो यह स्पष्ट नहीं होता कि जिम्मेदार कौन है — प्रोग्रामर, ऑपरेटर या सरकार।
- **प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता:** मानव निर्णय, सहानुभूति और संदर्भात्मक समझ की अनदेखी का जोखिम।
- **साइबर सुरक्षा खतरे:** एआई प्रणालियाँ हैकिंग, हेरफेर या विरोधी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं।

- विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भरता: यदि भारत बाहरी एआई कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर होता है तो “डिजिटल उपनिवेशवाद” का खतरा।

सरकारी पहल

- इंडियाएआई मिशन (2024): पाँच वर्षों में ₹10,300 करोड़ का बजट।
 - एक प्रमुख लक्ष्य है 18,693 GPUs के साथ उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण।



- भारत के एआई मॉडल्स और भाषा तकनीकें: सरकार भारत की अपनी आधारभूत मॉडल्स विकसित कर रही है, जिनमें बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं।
- भारतजेन: विश्व का प्रथम सरकारी वित्तपोषित मल्टीमॉडल LLM पहल, 2024 में शुरू किया गया।
- सर्वम-1 एआई मॉडल: भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित बड़ा भाषा मॉडल, जिसमें 2 अरब पैरामीटर्स हैं और यह 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
- हनुमान का एवेरेस्ट 1.0: SML द्वारा विकसित बहुभाषी एआई प्रणाली, जो 35 भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और इसे 90 तक बढ़ाने की योजना है।
- भाषिणी: एक एआई-संचालित प्लेटफॉर्म जो कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद और वाणी उपकरण प्रदान करके भाषा बाधाओं को दूर करता है।

- एआई उत्कृष्टता केंद्र: पूरे देश में एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए समर्पित एआई हब एवं नवाचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी क्षेत्र के नवाचार को मिलाकर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाता है।
 - आधार, UPI और डिजिलॉकर भारत के DPI की नींव हैं।
 - वित्तीय और शासन प्लेटफॉर्म में बुद्धिमान समाधान एकीकृत किए जा रहे हैं ताकि DPI को बेहतर बनाया जा सके।
- ई-कोर्ट्स परियोजना: भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यों को डिजिटल नवाचार के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई।
 - चरण III: केस प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए उन्नत एआई समाधान एकीकृत करता है।

निष्कर्ष

- कंप्यूटिंग अवसंरचना का विस्तार करने से लेकर घरेलू मॉडल्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने तक, देश एक सुदृढ़ एआई इकोसिस्टम बना रहा है जो नागरिकों को लाभ पहुंचाता है और नवाचार को आगे बढ़ाता है।
- कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में पहलें व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करती हैं जिनका वास्तविक प्रभाव है।
- ये प्रयास भारत को एक वैश्विक एआई नेता के रूप में उभरने और “विकसित भारत 2047” की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सुदृढ़ नींव रखते हैं।

स्रोत: TH

भारत के डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण

समाचारों में

- भारत डेयरी क्षेत्र में किसानों की उत्पादकता, पारदर्शिता और सहयोग बढ़ाने के लिए तेजी से डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहा है।

भारत के डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण

- भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा है।
- यह अपने डेयरी क्षेत्र को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आधुनिक बना रहा है, जिससे उत्पादकता, पारदर्शिता और किसानों का कल्याण बढ़ रहा है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जो किसानों, सहकारी समितियों और हितधारकों को जोड़कर संचालन में सुधार, अक्षमताओं को कम करने एवं डेयरी मूल्य श्रृंखला में ट्रेसबिलिटी बढ़ाने का कार्य कर रहा है।

विभिन्न कदम

- **राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM):** NDDB द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के सहयोग से लागू किया गया। यह “भारत पशुधन” नामक एकीकृत डिजिटल पशुधन पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में बड़ा कदम है।
 - भारत पशुधन डेटाबेस प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, स्वास्थ्य सेवाएँ, टीकाकरण और उपचार जैसी फील्ड गतिविधियों को दर्ज करता है।
 - सभी पशुओं को 12 अंकों का “पशु आधार” टैग दिया गया है, जिससे टीकाकरण, प्रजनन और उपचार का रिकॉर्ड रखा जा सके। नवंबर 2025 तक 35.68 करोड़ आईडी जारी किए जा चुके हैं।
 - किसान 1962 ऐप या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से रिकॉर्ड और पशु चिकित्सा सेवाओं व योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **स्वचालित दूध संग्रह प्रणाली (AMCS):** यह डेयरी सहकारी समितियों में दूध संग्रह को डिजिटलीकृत करती है, जिसमें मात्रा, गुणवत्ता और वसा सामग्री दर्ज होती है तथा किसानों को तुरंत भुगतान किया जाता है।
 - यह पारदर्शिता, ट्रेसबिलिटी और रीयल-टाइम अपडेट सुनिश्चित करती है, साथ ही सहकारी समितियों को डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

- 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालित, AMCS 26,000 से अधिक समितियों और 17.3 लाख किसानों को 54 मिल्क यूनियनों के माध्यम से सेवा देती है।
- **NDDB डेयरी ERP (NDERP):** यह एक व्यापक, वेब-आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से डेयरी और खाद्य तेल उद्योगों के लिए विकसित एवं अनुकूलित किया गया है।
- **सीमन स्टेशन प्रबंधन प्रणाली (SSMS):** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फ़ोजन सीमन डोज़ (FSD) के उत्पादन को सुव्यवस्थित करता है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (MSP) एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन सुनिश्चित करता है।
 - इसमें बैल जीवनचक्र प्रबंधन, सीमन उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, जैव सुरक्षा, फार्म और चारे का प्रबंधन तथा बिक्री ट्रैकिंग शामिल है।
 - यह सूचना नेटवर्क फॉर सीमन प्रोडक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट (INSPRM) से जुड़ा है, जो सीमन स्टेशनों और फील्ड-स्तरीय प्रणालियों जैसे INAPH (एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ नेटवर्क) के बीच रीयल-टाइम डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है।
 - इसे राष्ट्रीय डेयरी योजना I (NDP I) के अंतर्गत विकसित किया गया, जो NDDB द्वारा लागू विश्व बैंक वित्तपोषित पहल है।
- **इंटरनेट-आधारित डेयरी सूचना प्रणाली (i-DIS):** यह डेयरी सहकारी समितियों, यूनियनों और महासंघों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिससे दूध खरीद, बिक्री, उत्पादन और इनपुट्स पर डेटा एकत्र, साझा एवं विश्लेषित किया जा सके।
 - 198 मिल्क यूनियनों, 29 डेयरियों, 54 पशु-चारा संयंत्रों और 15 महासंघों की भागीदारी के साथ, i-DIS एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाती है, जो साक्ष्य-आधारित योजना, बेंचमार्किंग एवं नीति-निर्माण का समर्थन करती है।

- **दूध मार्ग अनुकूलन:** NDDDB ने GIS तकनीक का उपयोग करके दूध मार्ग अनुकूलन शुरू किया है, जिससे भारत की डेयरी आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल और किफायती बन सके।
- खरीद और वितरण मार्गों को डिजिटल रूप से मैप करके, सहकारी समितियाँ परिवहन दूरी, ईंधन लागत एवं डिलीवरी समय कम कर सकती हैं।
- विदर्भ मराठवाड़ा, वाराणसी, पश्चिम असम, झारखंड और इंदौर जैसे क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं ने उल्लेखनीय बचत दिखाई है।

महत्व

- एआई, IoT सेंसर, ब्लॉकचेन और मोबाइल ऐप्स का उपयोग पशुओं के स्वास्थ्य, दूध की गुणवत्ता एवं आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स की रीयल-टाइम निगरानी सक्षम करता है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे भुगतान, पशु चिकित्सा सेवाएँ और बाजार मूल्य तक पहुँचने में सहायता करते हैं, जिससे मध्यस्थों पर निर्भरता कम होती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करते हैं, जो निर्यात और उपभोक्ता विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- छोटे किसान भारत के अधिकांश दूध का उत्पादन करते हैं, जिससे मानकीकरण और डिजिटल एकीकरण कठिन हो जाता है।
- कई ग्रामीण उत्पादकों को ऐप्स और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने का प्रशिक्षण नहीं है।
- खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोल्ड चेन सुविधाएँ और ग्रामीण विद्युतीकरण अपनाने में बाधा डालते हैं।
- IoT उपकरणों, सेंसर और स्वचालित प्रणालियों में उच्च प्रारंभिक निवेश छोटे किसानों के लिए वहन योग्य नहीं है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत का डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDDB) के नेतृत्व में एक बड़े डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है।

- सहकारी क्षमता को डिजिटल नवाचार के साथ मिलाकर, भारत एक ट्रेस करने योग्य, कुशल और सतत डेयरी मूल्य श्रृंखला बना रहा है।
- यह परिवर्तन केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है, जो ग्रामीण परिवारों को सशक्त बना रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहा है। इसे डिजिटल इंडिया जैसी नीतिगत पहलों का समर्थन प्राप्त है।

स्रोत : PIB

जिला-प्रेरित वस्त्र रूपांतरण (DLTT) योजना

संदर्भ

- वस्त्र मंत्रालय ने “जिला-प्रेरित वस्त्र रूपांतरण (DLTT)” पहल की घोषणा की है। यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को उत्प्रेरित करना है।

परिचय

- मंत्रालय की योजना है कि 100 उच्च-क्षमता वाले जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन बनाया जाए और 100 आकांक्षी जिलों को स्वावलंबी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए।
- इसके लिए जिला-स्तरीय, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- मंत्रालय ने सभी जिलों का विश्लेषण तीन प्रमुख मानकों — निर्यात प्रदर्शन, MSME पारिस्थितिकी तंत्र, कार्यबल उपस्थिति — पर आधारित डेटा-आधारित स्कोरिंग पद्धति से किया।
- पहल पूर्वोदय (Purvodaya) अभिसरण पर भी बल देती है, विशेषकर पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में।

जिलों की श्रेणीकरण की दो-आयामी रणनीति

- चैंपियन जिले (पैमाना और परिष्कार):
 - इन जिलों का ध्यान उन्नत बाधाओं को दूर करने पर होगा।

- हस्तक्षेपों में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFCs) का उन्नयन, इंडस्ट्री 4.0 का एकीकरण, और प्रत्यक्ष निर्यात बाजार संपर्क शामिल हैं।
- **आकांक्षी जिले (आधार और औपचारिकता):**
 - इन जिलों का लक्ष्य बुनियादी स्तर से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा।
 - इसमें बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन, कच्चे माल के बैंक स्थापित करना, तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) व सहकारी समितियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है।
- **2023-24 में भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और परिधान (T&A) सहित हस्तशिल्प का हिस्सा 8.21% रहा।**
- **कच्चे माल का उत्पादन:** भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास और जूट उत्पादक है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक भी है। विश्व के 95% हाथ से बुने कपड़े भारत से आते हैं।
- **रोजगार सृजन:** यह उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोजक है, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 10 करोड़ लोगों को सहायक क्षेत्रों में रोजगार देता है।

DLTT पहल का महत्व

- यह पहल विकेंद्रीकृत और जिला-विशिष्ट औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे “एक ही पैटर्न” वाले दृष्टिकोण से हटकर स्थानीय ताकतों, संसाधनों एवं कौशल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है।
- DLTT भारत की वस्त्र निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करता है, जिससे सक्षम जिलों को पैमाना बढ़ाने, तकनीक उन्नत करने और सीधे वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलता है।
- MSMEs और अनौपचारिक उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने से वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र का औपचारिकरण होता है, जिससे छोटे उत्पादकों, कारीगरों एवं सूक्ष्म उद्यमियों को वित्त, तकनीक तथा बाजार तक बेहतर पहुँच मिलती है।
- DLTT स्थानीय उत्पादन केंद्रों को विकसित करके आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाता है और केंद्रित विनिर्माण क्षेत्रों पर निर्भरता कम करता है।
- **क्षेत्रीय केंद्र:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड एवं गुजरात भारत के शीर्ष वस्त्र और परिधान निर्माण राज्य हैं।

वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की अन्य पहल

- **PM MITRA पार्क योजना:** इसका उद्देश्य भारत में 7 मेगा एकीकृत वस्त्र पार्क विकसित करना है (तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में)।
 - इसका लक्ष्य आधुनिक, एकीकृत, विश्वस्तरीय “प्लग एंड प्ले” वस्त्र अवसंरचना बनाना है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** जापानी निवेश भारत के “मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड” और “चाइना-प्लस-वन” विनिर्माण रणनीतियों के साथ अच्छी तरह सामंजस्यशील है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह योजना मानव-निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई।
- **निर्यात संवर्धन परिषदें (EPCs):** वस्त्र और परिधान मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 EPCs हैं, जिनमें फाइबर से लेकर तैयार माल एवं पारंपरिक क्षेत्रों जैसे हैंडलूम, हस्तशिल्प तथा कालीन शामिल हैं।

भारत का वस्त्र क्षेत्र

- **घरेलू व्यापार में योगदान:** भारत का घरेलू परिधान और वस्त्र उद्योग देश के GDP में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% एवं निर्यात में 12% योगदान देता है।
- **वैश्विक व्यापार में हिस्सा:** भारत का वस्त्र और परिधान वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सा है।
- **निर्यात:** भारत विश्व का 6वाँ सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक है।

भारत के वस्त्र क्षेत्र की चुनौतियाँ

- यह क्षेत्र अत्यधिक खंडित है, जिसमें छोटे और अनौपचारिक उद्यम प्रमुख हैं, जो पैमाना बढ़ाने, तकनीक अपनाने एवं औपचारिक वित्त तक पहुँच में बाधाओं का सामना करते हैं।
- पुरानी उत्पादन प्रथाओं, सीमित औपचारिक प्रशिक्षण और अपर्याप्त उद्योग-शैक्षणिक संबंधों के कारण श्रम उत्पादकता एवं कौशल अंतराल बने हुए हैं।
- भारत उच्च लॉजिस्टिक्स और लेन-देन लागत तथा सीमा शुल्क स्वकृति में देरी का सामना करता है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा कम होती है।
- MSMEs और हैंडलूम इकाइयों के लिए सस्ती ऋण तक पहुँच एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

आगे की राह

- सुदृढ़ ब्रांडिंग, डिजाइन और विपणन समर्थन आवश्यक है ताकि जिले अनुबंध विनिर्माण से अपने ब्रांड एवं भौगोलिक संकेतक आधारित उत्पादों की ओर बढ़ सकें।
- निर्यात प्रदर्शन, रोजगार सृजन और औपचारिककरण संकेतकों के आधार पर नियमित प्रभाव मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम सुधार को संस्थागत किया जाना चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा प्रणालियों का उपयोग जिला स्तर पर उत्पादन, कौशल परिणाम, निर्यात एवं बाजार संपर्कों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ 2026

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ (WESP) 2026 रिपोर्ट ने भारत की GDP वृद्धि दर को 2025 में 7.4 प्रतिशत से घटकर 2026 में 6.6 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए टैरिफ बताए गए हैं।

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा तैयार की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- **वैश्विक वृद्धि परिदृश्य:** विश्व उत्पादन 2026 में घटकर 2.7% रहने का अनुमान है, जो 2027 में बढ़कर 2.9% हो सकता है।
- अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में घरेलू मांग एवं नीतिगत ढील गतिविधियों को समर्थन दे रही है, जबकि यूरोप में वृद्धि कमजोर बनी हुई है।
- उच्च ऋण और जलवायु झटके कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं।
- **व्यापार और निवेश प्रवृत्तियाँ:** 2025 में वैश्विक व्यापार अपेक्षा से बेहतर रहा, जिसका कारण उच्च टैरिफ से पहले की गई अग्रिम शिपमेंट और सुदृढ़ सेवाओं का निर्यात था। लेकिन 2026 में वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।
- **मुद्रास्फीति और जीवन-यापन लागत:** वैश्विक शीर्षक मुद्रास्फीति 2025 के 3.4% से घटकर 2026 में 3.1% रहने की संभावना है। हालांकि, ऊँची कीमतें वास्तविक आय को कम करती रहेंगी, विशेषकर निम्न-आय वाले परिवारों के लिए।
- **वित्तीय स्थिति और जोखिम:** कम ब्याज दरें और बेहतर बाजार भावना ने पूंजी प्रवाह को पुनर्जीवित करने में सहायता की है, लेकिन उच्च परिसंपत्ति मूल्यांकन और बढ़ी हुई उधारी लागत जोखिम बने हुए हैं।
- कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ भारी ऋण भार और सस्ती वित्त तक सीमित पहुँच से बाधित हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण

- **मुद्रास्फीति:** शीर्षक मुद्रास्फीति अपने चरम से कम हुई है, लेकिन सेवाओं में मूल मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है।
- **बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद:** ऊँचे शुल्क, व्यापार बाधाएँ और नीतिगत अनिश्चितता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है तथा व्यापार वृद्धि को धीमा किया है।

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** वृद्ध होती जनसंख्या, कम उत्पादकता वृद्धि और धीमी तकनीकी प्रसार दीर्घकालिक वृद्धि पर भार डाल रहे हैं।
- **कमजोर बहुपक्षीय सहयोग:** वैश्विक शासन और व्यापार नियमों का विखंडन नीति समन्वय एवं वृद्धि की गति को कम कर रहा है।

प्रमुख सिफारिशें

- **मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों में समन्वय:** केवल मौद्रिक नीति लगातार मूल्य दबावों को नियंत्रित नहीं कर सकती।
 - मुद्रास्फीति को स्थिर करने, निवेश को समर्थन देने और कमजोर समूहों की रक्षा करने के लिए मौद्रिक, राजकोषीय एवं औद्योगिक नीतियों के बीच बेहतर सामंजस्य आवश्यक है।
- **राजकोषीय नीति का रणनीतिक और विश्वसनीय उपयोग:** विश्वसनीय मध्यम-अवधि की राजकोषीय योजनाएँ और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन राजकोषीय स्थान को पुनर्निर्मित करने के लिए आवश्यक हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग और विकास वित्त: सेविला प्रतिबद्धता** के अंतर्गत किए गए वादों को लागू करना, जिसमें ऋण सुधार और रियायती व जलवायु वित्त का विस्तार शामिल है, निवेश अंतराल को बंद करने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **खुली नियम-आधारित व्यापार प्रणाली:** वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और सहयोग को सुदृढ़ करना वृद्धि बनाए रखने और बढ़ती अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था में विखंडन को सीमित करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है।

स्रोत: UN

हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में DRDO की बड़ी सफलता

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

परिचय

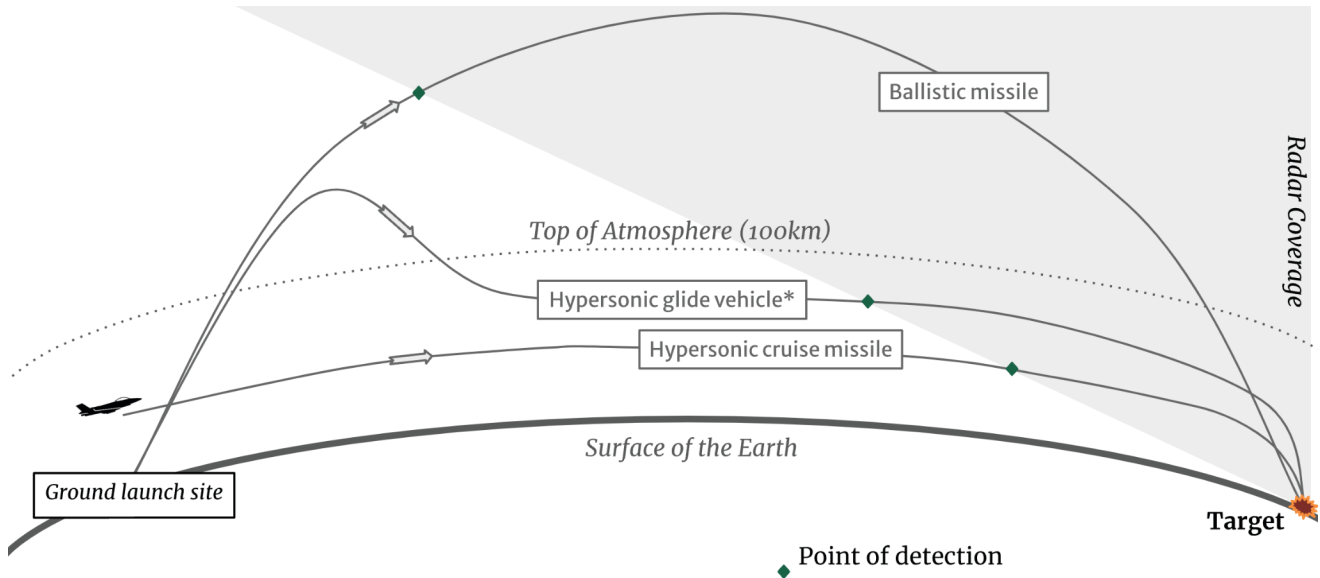
- DRDO ने अपने एक्टिवली कूल्ड स्क्रेमजेट फुल स्केल कंबस्टर का अत्याधुनिक स्क्रेमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में एक विस्तृत दीर्घकालिक ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया।
- इस परीक्षण में 12 मिनट से अधिक का रन टाइम प्राप्त किया गया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) द्वारा किया गया, जो हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख सुविधा है और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों एवं तकनीकों के डिज़ाइन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है।

हाइपरसोनिक मिसाइलें

- हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से पाँच गुना अधिक (6,100 किमी/घंटा से अधिक) गति लंबे समय तक प्राप्त करने में सक्षम है।
- यह गति अत्याधुनिक एयर-ब्रीदिंग इंजन के माध्यम से प्राप्त होती है, जो सुपरसोनिक दहन का उपयोग करके दीर्घकालिक उड़ान को बनाए रखता है।
- ये मिसाइलें अधिक मैन्युवरेबल होती हैं, जिससे वे वायु रक्षा प्रणालियों से बच निकलने में अधिक सक्षम होती हैं।
- हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों के दो प्रकार हैं:
 - **हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs):** इन्हें रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और फिर लक्ष्य तक ग्लाइड करते हैं।
 - **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें (HCMs):** ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद एयर-ब्रीदिंग हाई-स्पीड इंजन या 'स्क्रेमजेट्स' द्वारा संचालित होती हैं।

भारत में मिसाइल प्रणालियों के प्रकार

- **बैलिस्टिक मिसाइलें:**
 - बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक पेलोड (सामान्यतः वारहेड) पहुँचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का उपयोग करती हैं।



- अपनी लंबी दूरी की क्षमता और बड़े पेलोड के कारण, बैलिस्टिक मिसाइलें एक राष्ट्र की सामरिक रक्षा स्थिति में निवारक के रूप में कार्य करती हैं।
- शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें (SRBM): पृथ्वी I, II, III
- मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें (MRBM): अग्नि-I, II, III, IV, V

लक्ष्यों को न्यूनतम सहायक क्षति के साथ समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

- लॉन्ग-रेंज क्रूज मिसाइल: निर्भया
- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल: ब्रह्मोसा

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

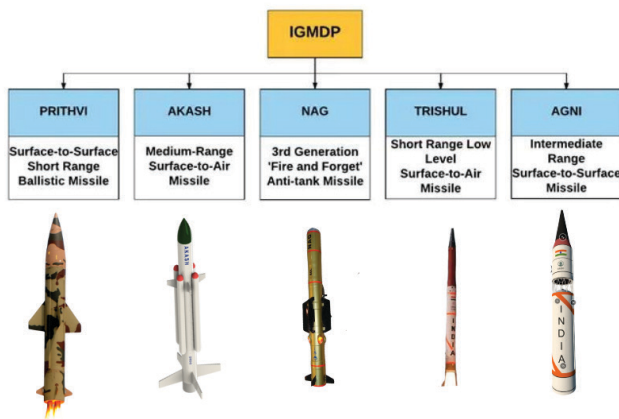
शक्सगाम घाटी

संदर्भ

- भारत ने पुनः दोहराया है कि शक्सगाम घाटी उसकी संप्रभु क्षेत्र का भाग है और 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अवैध और अमान्य बताया है।
- भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का भी विरोध दोहराया है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जो अवैध कब्जे में है।

शक्सगाम घाटी के बारे में

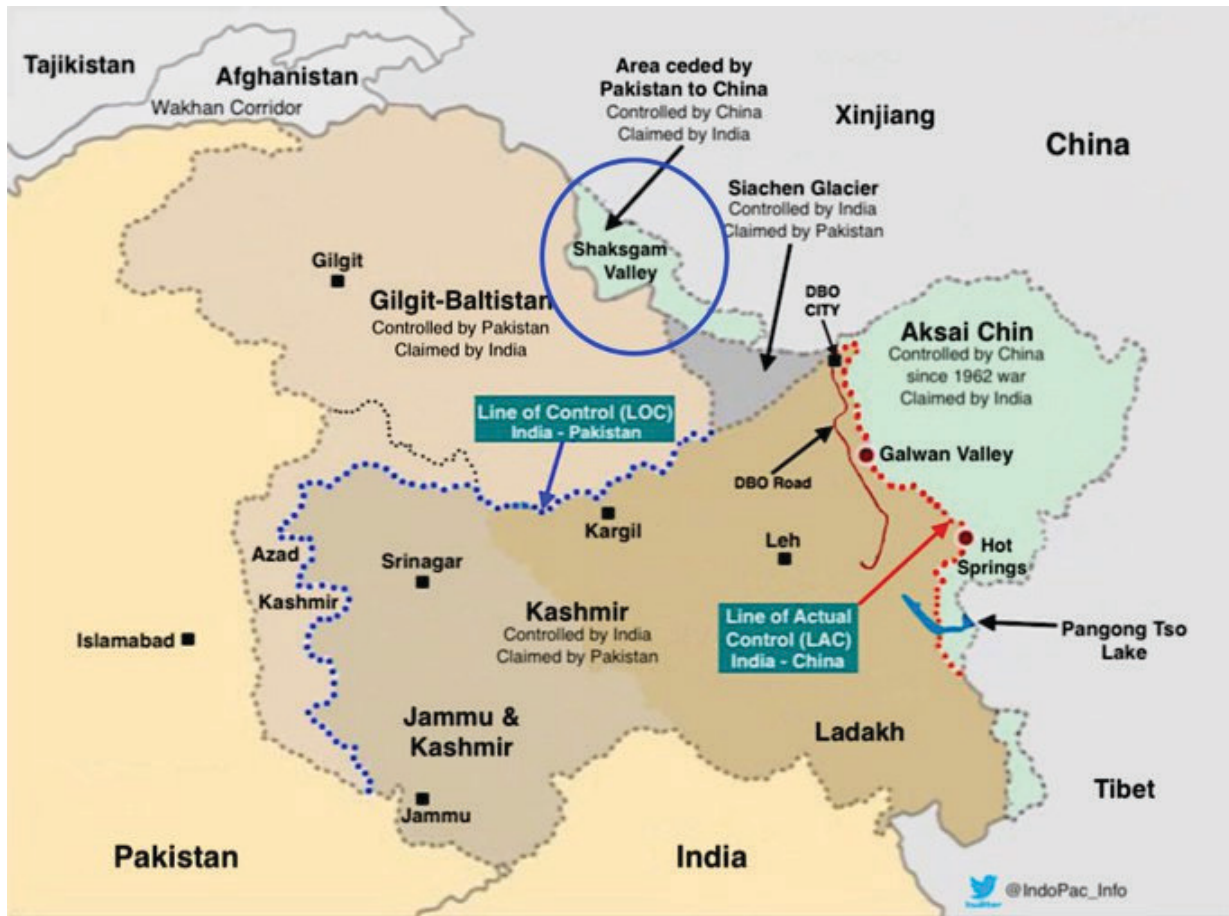
- इसे ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है।
- ऐतिहासिक रूप से यह जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा रहा है।



क्रूज मिसाइलें:

- क्रूज मिसाइलें निर्देशित मिसाइलें होती हैं जो वायुगतिकीय लिफ्ट का उपयोग करके वायुमंडल में यात्रा करती हैं, सामान्यतः सबसोनिक या सुपरसोनिक गति पर।
- अपनी सटीकता और लचीलापन के कारण, क्रूज मिसाइलें प्रायः सामरिक परिस्थितियों में विशिष्ट

- वर्तमान में यह चीनी नियंत्रण में है। पाकिस्तान ने 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के बाद शक्सगाम घाटी को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था।



स्रोत: TOI

जल वाष्प

संदर्भ

- हालिया अध्ययन के अनुसार, जल वाष्प वायुमंडलीय ऊष्मन में एरोसोल्स की तुलना में अधिक योगदान देता है, जो क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली में इसकी प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- जल वाष्प का विकिरण प्रभाव एरोसोल्स की उपस्थिति से गहराई से प्रभावित होता है, जो एरोसोल-जल वाष्प के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है।
- जल वाष्प विकिरण प्रभाव (WVRE) स्वच्छ (कम एरोसोल) वायुमंडलीय परिस्थितियों में सबसे अधिक होता है, सतह और वायुमंडल दोनों में।

- इंडो-गंगा का मैदानी क्षेत्र (IGP) एरोसोल लोडिंग का वैश्विक हॉटस्पॉट है, इसके कारण:

- उच्च जनसंख्या घनत्व;
- औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन;
- बायोमास जलाना और धूल का परिवहन।

जल वाष्प

- जल वाष्प वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीनहाउस गैस है।
- यह एक संघननीय गैस है, जो आसानी से गैस से तरल में परिवर्तित हो जाती है।
- इसकी सांद्रता ऊँचाई के साथ और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है।
- यह गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आयतन के अनुसार हवा का 4% तक हो सकता है।

- ठंडे, शुष्क रेगिस्तानों और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह 1% से भी कम हो सकता है।

स्रोत: TH

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

समाचारों में

- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मंदिर के पुनः उद्घाटन की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

- यह सोमनाथ मंदिर पर प्रथम दर्ज की गई आक्रमण की 1,000वीं वर्षगांठ और 1951 में इसके पुनः उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।
 - मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्या बाई होल्कर जैसे भक्तों के सामूहिक संकल्प से हुआ।
- यह चार दिवसीय आयोजन है, जिसमें 72 घंटे का अखंड ओंकार जाप, भक्ति संगीत, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।
- यह सोमनाथ को विनाश की स्मृति के बजाय पुनरुत्थान और राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है।

सोमनाथ

- सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। इसे भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है।
- सोमनाथ को भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है।
- वर्तमान मंदिर परिसर में गर्भगृह (संरक्षित कक्ष), सभामंडप (सभा भवन) और नृत्यमंडप (नृत्य भवन) शामिल हैं, जो अरब सागर के किनारे भव्यता से खड़े हैं।
- विशेषताएँ: मंदिर 150 फुट ऊँचे शिखर से सुशोभित है, जिसके शीर्ष पर 10 टन का कलश है। 27 फुट ऊँचा ध्वजदंड मंदिर की अटल पहचान को दर्शाता है।
- परिसर में 1,666 स्वर्ण-लेपित कलश और 14,200 ध्वजाएँ हैं, जो पीढ़ियों की भक्ति एवं शिल्पकला का प्रतीक हैं।

- **आक्रमण:** सदियों में इसे बार-बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया, जिसकी शुरुआत 1026 में महमूद गजनवी के पूर्व दर्ज आक्रमण से हुई। यह भारत की अटूट आस्था, पहचान और सभ्यतागत गर्व का प्रतीक है।
- **पुनर्निर्माण:** वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में हुआ और मई 1951 में पूरा हुआ। इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पूरा कराया गया।

स्रोत: PIB

वेइमार त्रिकोण

समाचारों में

- भारत ने प्रथम बार वेइमार त्रिकोण प्रारूप में भाग लिया, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास है।

वेइमार त्रिकोण के बारे में

- यह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का त्रिपक्षीय राजनीतिक और कूटनीतिक समूह है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
- इसका नाम वेइमार शहर पर रखा गया है, जहाँ इन तीन देशों के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक हुई थी।
- इसका उद्देश्य एकजुट, सुरक्षित और लचीला यूरोप का निर्माण करना तथा पश्चिमी एवं मध्य यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना है।

भारत की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह भारत-यूरोप रणनीतिक अभिसरण को दर्शाता है, द्विपक्षीय संबंधों से परे।
- यह यूरोप के भारत के प्रति समर्थन को इंगित करता है, जैसे:
 - ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताएँ
 - स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय
- यह भारत की प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म के साथ भागीदारी का विस्तार करता है, भले ही वे औपचारिक यूरोपीय संघ संरचनाओं से बाहर हों।

स्रोत: TH

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 75 परियोजनाएँ पूर्ण

संदर्भ

- पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 75 परियोजनाएँ पूरी कीं।

परिचय

- पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य थीम-आधारित पर्यटन सर्किट का विकास करना है।
 - यह योजना पर्यटन विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें अवसंरचना निर्माण, गंतव्य प्रबंधन एवं आगंतुक अनुभव पर ध्यान दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल 76 परियोजनाएँ 5290.33 करोड़ रुपये की राशि से स्वीकृत की गई हैं।
- थीम-आधारित पर्यटन सर्किट** : यह विभिन्न विषयों पर आधारित सर्किट की पहचान करती है, जैसे:
 - आध्यात्मिक सर्किट (जैसे चार धाम यात्रा, बौद्ध सर्किट)
 - सांस्कृतिक सर्किट (जैसे उत्तर-पूर्व सर्किट, जनजातीय सर्किट)
 - विरासत सर्किट
 - वन्यजीव सर्किट
 - तटीय सर्किट
- अब इस योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य सतत और जिम्मेदार गंतव्यों का विकास करना है।

स्रोत: PIB

समग्र शिक्षा 3.0

संदर्भ

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा 3.0 पर हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसका शीर्षक था 'रीइमेजनिंग समग्र शिक्षा'।

परिचय

- बैठक का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सहयोगात्मक विचार-विमर्श के माध्यम से समग्र शिक्षा 3.0 के लिए एक रणनीतिक, परामर्शात्मक एवं क्रियान्वयन योग्य रोडमैप तैयार करना था।
- चर्चाओं में उभरती चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्राथमिक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो शासन, अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण एवं छात्र अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हैं।

समग्र शिक्षा

- प्रारंभ**: इसे केंद्रीय बजट 2018-19 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य**: स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखना, बिना किसी विभाजन के, प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक।
- यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करता है:
 - सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
 - शिक्षक शिक्षा (TE)
- योजना के मुख्य परिणामों में सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को सुदृढ़ करना शामिल है।
- यह योजना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाती है।

स्रोत: TH

क्रिएटर्स कॉर्नर

समाचारों में

- प्रसार भारती ने डिजिटल प्रतिभा को उजागर करने के लिए DD News पर "क्रिएटर्स कॉर्नर" लॉन्च किया।

क्रिएटर्स कॉर्नर

- यह DD न्यूज़ पर एक नया खंड है जिसका उद्देश्य भारत भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

- यह छोटे शहरों और भाषाई समुदायों के उन क्रिएटर्स को सशक्त करेगा जो स्वतंत्र रूप से कंटेंट का निर्माण, संपादन एवं वितरण कर रहे हैं।
- इसमें समाचार और सामयिक घटनाएँ, संस्कृति, यात्रा, भोजन, कला एवं साहित्य, संगीत एवं नृत्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रेरणादायक कहानियाँ, पर्यावरण एवं सतत विकास, तथा मनोरंजन जैसे विविध विषयों पर सामग्री प्रस्तुत की जाएगी।

महत्व

- यह देश की बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी को पहचानने और मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
- यह एक जीवंत, उत्तरदायी और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है जो क्रिएटर्स को पूर्ण कंटेंट उत्पादक के रूप में मान्यता देता है।
- इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण को प्रोत्साहित करके और प्रसार भारती व व्यक्तिगत कंटेंट क्रिएटर्स के बीच साझेदारी के माध्यम से इसकी पहुँच का विस्तार करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

स्रोत: PIB

9वीं शीर्ष-स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) बैठक

समाचारों में

- गृहमंत्री ने नई दिल्ली में 9वीं शीर्ष-स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) बैठक की अध्यक्षता की और देश में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास की समीक्षा की।

NCORD के बारे में

- NCORD भारत का प्रमुख समन्वय तंत्र है जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाकर मादक पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग से निपटता है।
- इसे 2016 में स्थापित किया गया और 2019 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया।

- यह NDPS अधिनियम, 1985 को एक संरचित चार-स्तरीय प्रणाली (शीर्ष समिति, कार्यकारी समिति, राज्य स्तरीय समितियाँ और जिला स्तरीय समितियाँ) के माध्यम से लागू करता है।

मुख्य पहलें

- **NCORD पोर्टल:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा विकसित, यह खुफिया जानकारी साझा करने और निगरानी के लिए एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली है।
- **MANAS हेल्पलाइन (1933):** नशीली दवाओं से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए 24x7 टोल-फ्री सेवा।
- **NIDAAN डेटाबेस:** गिरफ्तार नार्को-अपराधियों को ट्रैक करता है ताकि नेटवर्क को बाधित किया जा सके।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) – NSG

समाचारों में

- गृहमंत्री ने राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) लॉन्च की, जो देश की काउंटर-IED और आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS)

- इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देशभर में बम विस्फोट से संबंधित घटनाओं का सटीक और संगठित विश्लेषण किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह, संकलन और प्रसार सक्षम करना है।
- यह ATS इकाइयों, पुलिस एवं CAPFs को ऑनलाइन उपलब्ध व्यापक डेटा तक पहुँचने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
- यह प्रणाली दो-तरफ़ा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी।

स्रोत: Air

तांबा (Copper)

संदर्भ

- वैश्विक तांबे की मांग 2040 तक लगभग 50% बढ़ने का अनुमान है, जिसका कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण और बढ़ता रक्षा व्यय है।

तांबे के बारे में

- तांबा (Cu) एक लाल-नारंगी, नरम और अत्यधिक लचीला धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 29 है।
- यह अपनी असाधारण विद्युत और तापीय चालकता के लिए जाना जाता है।

- ये गुण इसे विद्युत तारों, विद्युत संचरण, पाइपलाइन और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक बनाते हैं।
- तांबा पीतल (तांबा-जस्ता) और कांस्य (तांबा-टिन) जैसे महत्वपूर्ण मिश्रधातुओं का प्रमुख घटक है, जो सुदृढ़ता और संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाते हैं।
- भारत में तांबे के महत्वपूर्ण अयस्क संसाधन मुख्यतः राजस्थान के खेड़ी बेल्ट, मध्य प्रदेश के मलांजखण्ड और झारखंड के सिंहभूम बेल्ट में पाए जाते हैं।

स्रोत: FP

■■■■

